been referred to the Wage Boards for Working Journalists and Non-Journalists Newspaper and News Agency employees.

(b) Wage Boards which met for the first time on 3.4.95 did not make any recommendation on the issue of Interim Relief.

(c) Does not arise.

Compulsory Presence of Employers in Labour Courts

3197. SHRI SANJAY DALMIA:

SHRI K. M. KHAN:

Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the factory owners are not presenting themselves in the courts on the dates of hearing in labour disputes;

(b) if so, whether Government propose to take any steps to ensure the presence of factory owners in courts on due dates for speedy disposal of cases;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवा

3198. **श्री अजीत जोगी :**

श्री जगन्नाथ सिंह :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों पंजीकृत बेरोगार युवाओं की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से शिक्षित और अशिक्षित युवाओं की संख्या कितनी है ;

(ग) विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) शहरी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं और उनकी तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगार का क्या अनुपात है ?

श्रम मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : नवीनतम उपलब्ध सूचनानुसार 31.1.1995 तक देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, 367.4 लाख थी ।

(ख) 31.12.1992 की स्थितिनुसार (नवीनतम उपलब्ध) देश में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर, शिक्षित (मैट्रिक तथा इससे अधिक) तथा अशिक्षित (अशिक्षित सहित मैट्रिक से कम) रोजगार चाहनेवालों की संख्या क्रमशः 230.1 तथा 137.5 लाख थी ।

(ग) 8वीं योजना की नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य उत्पादकारी रोजगार सृजन करना है । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना में कृषि विकास का भौगोलिक एवं फसलवार विविधीकरण कृषि आधारित एवं सहायक कार्यकलापों में विकास, गैर-कृषि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विनिर्माण कार्यकलापों तथा लघु एवं विकेन्द्रीकृत विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि को प्रोत्साहित करना अवसंरचना निर्माण कार्यक्रम तथा आवास कार्यक्रमों का विस्तार एवं सेवाओं के विकास हेतु प्रोत्साहन तथा अनौपचारिक कार्यकलापों पर विशेष बल दिया गया है ।

(घ) वर्ष 1987-88 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, सामान्य स्तर पर, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर (श्रम बल में प्रति 1000